AKRSP

Azim Premji University

अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय

COVID-19 आजीविका सर्वेक्षण

बिहार (ग्रामीण)

कोरोना-तालाबंदी के चलते, रोज़गार और आजीविका पर पड़े असर और इससे राहत पाने के लिए घोषित सरकारी योजनाओं को समझने के लिए, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम के साथ मिलकर बिहार के १७३ उत्तरदाताओं का एक विस्तृत फ़ोन सर्वेक्षण किया।

उत्तरदाताओं का चयन उद्देश्यपूर्ण विधि के द्वारा किया गया था जिससे उनके कार्य और स्थान में विविधता सुनिश्चित की जा सके। यह प्रतिदर्श (सैंपल) राज्य का प्रतिनिधित्व नहीं करता है।

राज्य के १० जिलों के उत्तरदाताओं का साक्षात्कार लिया गया। यहाँ प्रस्तुत डाटा १७ अप्रिल, २०२० और १२ मई, २०२० के बीच एकत्रित किया गया था। यह सर्वेक्षण परिणाम राज्य-स्तरीय संक्षिप्त जानकारी की एक श्रृंखला का हिस्सा है। विस्तृत जानकारी *cse.azimpremjiuniversity.edu.in* पर उपलब्ध है।

मुख्य निष्कर्ष

४६%
श्रमिकों ने अपना रोजगार खोया है।

१० में से ८
दिहाड़ी मज़दूरों ने अपना रोज़गार खोया है।

३७%
परिवारों के पास एक हफ्ते के लायक ज़रूरी सामान खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे।

६९%
परिवारों ने बताया कि पहले की तुलना में वो अब कम खाना खा रहे हैं।

७९%
वंचित परिवारों को राशन मिला।

१० में से ४
वंचित परिवारों को एक भी नकद अंतरण नहीं मिला।

राहत उपायों की घोषणा

एसएमएस के माध्यम से सर्वेक्षण उत्तरदाताओं को राहत उपाय की जानकारी भेजी गई थी।

केंद्रीय स्तर

* हर परिवार को प्रति व्यक्ति ५ किलो अनाज (चावल/गेहूँ) और प्रति परिवार १ किलो दाल अप्रेल से जून 2020 तक हर महीने मुफ्त दिया जाएगा । यह नियमित राशन के अतिरिक्त है जो उन्हें मिलता रहेगा।
* अप्रेल से जून 2020 तक, हर महीने, महिला जन धन खाता धारकों के खाते में Rs 500 की राशि जमा की जाएगी।
* पीएम-किसन योजना की प्रथम किश्त (रु २०००) अप्रैल महीने के पहले सप्ताह में दी जाएगी।

राज्य स्तर

* सभी कार्ड धारक परिवारों को अप्रैल में १००० रुपये और मुफ्त राशन दिया जाएगा।
* बिहार फाउंडेशन, दुसरे राज्यों मैं रह रहे प्रवासी बिहारी मज़दूरों को भोजन आश्रय और चिकित्सा सहायता प्रदान करवाएगा ।
* पेंशनरों को तीन महीने के लिए पेंशन का अग्रिम भुगतान प्राप्त होगा।
* छात्र छात्रवृत्ति 31 मार्च तक बैंक खातों में भेज दी जाएगी।
* कोविद -१९ उपचार में लगे स्वास्थ्य देखभाल कर्मी और डॉक्टरों को मौद्रिक प्रोत्साहन मिलेगा।

Source : covid19socialsecurity.wordpress.com/relief-measures

अनुशंसाएँ

* पीडीएस प्रणाली को सार्वभौमिक (यूनिवर्सल) बनाया जाना चाहिए और विस्तारित राशन को कम से कम अगले छह महीनों के लिए बांटना चाहिए।
* दो महीने के लिए कम से कम रु 7000 का नकद हस्तांतरण (ट्रांसफर) दिया जाना चाहिए। अर्थव्यवस्था में मांग को वापस लाने के लिए बड़े हस्तांतरण की आवश्यकता है।
* नकद हस्तांतरण की पहुंच का विस्तार करने के लिए मनरेगा, पीएम उज्जवला, पीडीएस और स्थानीय पंजीकरण से जानकारी का उपयोग करें।
* शहरी गरीबों के लिए कार्यक्रमों पर जोर देने की जरूरत है।
* मध्यम अवधि में, मनरेगा के विस्तार, शहरी रोजगार गारंटी की शुरुआत और सार्वभौमिक बुनियादी सेवाओं में निवेश जैसे सक्रिय कदमों की जरूरत है।

आजीविका पर प्रभाव

यह भाग तालाबंदी के चलते काम और कमाई पर पड़े असर को समझने की कोशिश करता है। तालाबंदी लागू होने के बाद के रोज़गार और कमाई की स्तरों को माप कर हमने इनकी तुलना फरवरी के आंकड़ों से की है।

चित्र १: : जिन श्रमिकों ने रोजगार खोया है (गतिविधि स्थिति के अनुसार) (%)

n = १५४

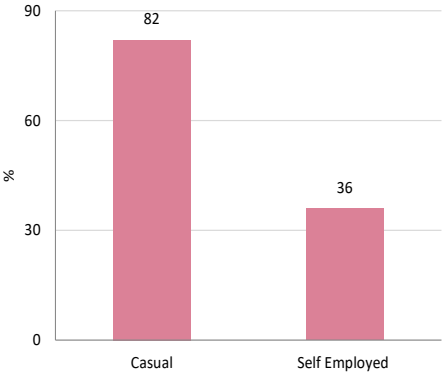

४६% ने बताया की उन्होंने तालाबंदी के दौरान अपना रोज़गार खो दिया।

५१% वंचित परिवारों ने अपना रोज़गार खोया है। ।

५८% अनुसूचित जाति / जनजाति के उत्तरदाताओं ने रोज़गार खो दिया।

८२% दिहाड़ा श्रामका न अपना राज़गार खाया, वह तालाबंदी से सबसे ज़्यादा प्रभावित हए हैं ।

पुरुषों की तुलना में अधिक महिलाओं ने अपनी नौकरी खोयी।

चित्र २: जिन्होंने अपना रोजगार खो दिया है (% लिंग के अनुसार) (%)

n = १५४

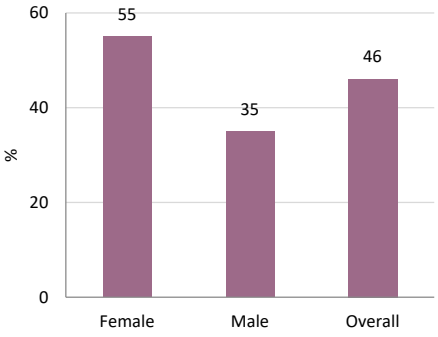

"सरकार हमें काम मुहैया कराए ताकि हम कमा सकें। मेरे पास एक MGNREGA कार्ड है और मैंने कार्यक्रम के तहत पहले काम किया है। सरकार को इस संकट के दौरान MGNREGA गतिविधियों को पुनः आरम्भ करनी चाहिए । इससे मुझे काफी मदद होगी "

(महिला, ४६, दिहाड़ी मज़दूर)

घरों पर प्रभाव

यह भाग यह देखता है परिवारों पर, खासकर उनके भोजन के सेवन अथवा कर्ज़े और बचत की स्तिथि पर, तालाबंदी के कारण क्या प्रभाव पड़ा।

चित्र ३: परिवारों पर प्रभाव (%)

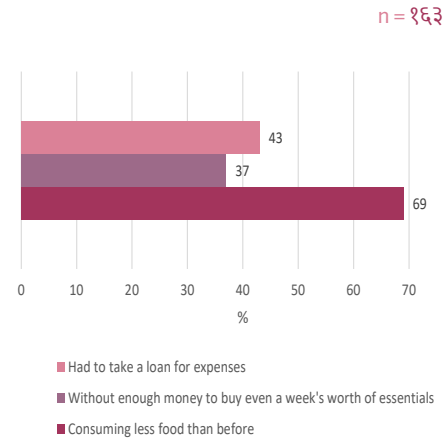

करीब १० में से ७ परिवारों ने बताया कि तालाबंदी के दौरान उन्होंने पहले कि तुलना में कम भोजन का सेवन कयिा।

अनुसूचित जाति/ जनजाति सबसे ज़्यादा प्रभावित। ८५% अनुसूचित जाति/ जनजाति के लोग पहले की तुलना में कम भोजन का सेवन कर रहे थे।

३७% परिवारों के पास एक हफ्ते के लायक ज़रूरी सामान खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे।

आधे से अधिक अनुसूचित जाति/ जनजाति परिवारों के पास एक हफ्ते के लायक ज़रूरी सामान खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे।

राहत योजनाओं की पहुँच

यह भाग सरकार द्वारा घोषित राहत उपायों की पहुंच और प्रभाव का अध्ययन करता है। हम राशन की उपलब्धता, लाभार्थियों को नकद हस्तांतरण और कमजोर परिवारों को मिलने वाले लाभों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

चित्र ५: वंचित परिवार जिन्हे तालाबंदी के दौरान राशन और जन धन ट्रांसफर मिला (%)

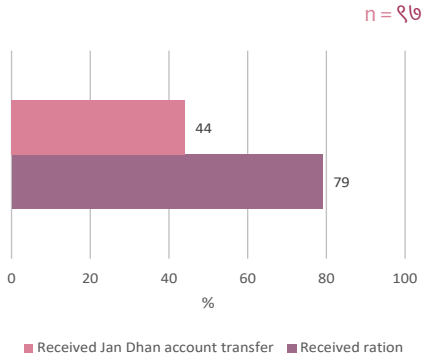

लगभग १० में से ८ वंचित परिवारों को तालाबंदी के दौरान राशन नहीं मिला।

५२% वंचित परिवारों के पास जन धन खाता नहीं था, ९२%खाताधारकों को नकद हस्तांतरण मिला।

४०%वंचित परिवारों को किसी भी प्रकार का नकदी हस्तांतरण नहीं मिला।

लगभग आधे किसानों को PM KISAN हस्तांतरण प्राप्त हुआ।

सर्वेक्षण कवरेज

४२% उत्तरदाता पुरुष थे और ५८% महिलाऐं।

८९%उत्तरदाता हिन्द थे और १०% मुस्लिम।

56% उत्तरदाता अन्य पिछड़े वर्ग के थे।

७९% वंचित परिवार थे, यानी उन्होंने फरवरी के महीने मैं १०,००० से कम कमाया।

चित्र ५: फरवरी के महीने में उत्तरदाताओं की गतिविधि की स्थिति (%)

n = १७३

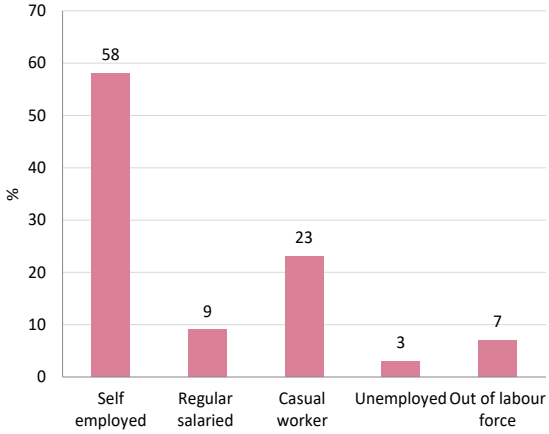

Results from other surveys happening in the state

* एक्शनएड द्वारा बिहार में किए गए तीव्र मूल्यांकन अध्ययन के अनुसार, 82 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अपनी नौकरी खो दी और अपने गृह जिलों में लौट आए।
* इंडस एक्शन द्वारा किए गए टेलीफोनिक सर्वेक्षण से पता चला कि इस राज्य में बेरोजगारी ९% पूर्व-लॉकडाउन से बढ़कर ६२% पोस्ट-लॉकडाउन में हो गई।
* डलबर्ग, ऑय डी इनसाइट ,ऑय ऑय टी-दिल्ली और सोसाइटी फॉर सोशल एंड इकनोमिक रिसर्च द्वारा आयोजित शोध में अन्य राज्यों के साथ-साथ बिहार पर पड़े कोरोना के प्रभाव की भी व्याख्या की गयी है।

देश भर में किए गए विभिन्न कोविड़-19 सर्वेक्षणों और अध्ययनों के संकलन के लिए कृपया देखें: *cse.azimpremjiuniversity.edu.in/covid19-analysis-of-impact-and-relief-measures/#other_surveys*

सवाल के लिए: **Centre for Sustainable Employment, Azim Premji University**
cse.azimpremjiuniversity.edu.in | cse@apu.edu.in